



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]

नई दिल्ली, शुक्रवार अक्टूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941

No. 338]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 03, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2019

(मामला सं. एसएसआर-09/2019)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित सोडियम सीट्रेट के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

फा. सं. 7/21/2019-डीजीटीआर : वर्ष 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन गण (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम सीट्रेट (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 14/23/2015-डी जी ए डी दिनांक 26 फरवरी, 2015 के द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 19/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 20 मई, 2015 द्वारा शुल्क लगाए गए थे।

2. और यतः मै. पोसी फार्माचेम प्रा.लि. (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक याचिका दायर की है जिसमें लागू संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ाने हेतु निणायक समीक्षा की शुरूआत की मांग की गई है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने का आरोप लगाया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "सोडियम सीट्रेट" "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद") है।
4. सोडियम सीट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो मोनो-सोडियम सीट्रेट, डाई सोडियम सीट्रेट और ट्राई सोडियम सीट्रेट के रूप में आता है। सोडियम सीट्रेट सीट्रिक एसिड का सोडियम साल्ट है। सीट्रिक एसिड की तरह यह स्वाद में खट्टा होता है। अन्य नमक की तरह इसका स्वाद भी नमकीन होता है। मूल पाटनरोधी जांच के दिनांक 26 फरवरी, 2015 के डी जी ए डी के अंतिम जांच परिणामों में पीयूसी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद सोडियम सीट्रेट है। "सोडियम सीट्रेट" एक रासायनिक यौगिक है जो मोनोसोडियम सीट्रेट, डाईसोडियम सीट्रेट और ट्राई सोडियम सीट्रेट के रूप में आता है। विचाराधीन उत्पाद का सौदा निम्नलिखित अन्य नामों से भी होता है- क सोडियम सीट्रेट ख. ट्राई सोडियम सीट्रेट ग. ट्राइ सोडियम सीट्रेट डीहाइड्रेट घ. सोडियम सीट्रेट डी हाइड्रेट ड. ट्राईबेसिक सोडियम सीट्रेट च. सोडियम सीट्रेट ट्राईबेसिक डीहाइड्रेट, छ. सोडियम सीट्रेट डाई बेसिक सेस्कीहाइड्रेट ज. सोडियम सीट्रेट मोनोबेसिक बायोक्स्ट्रा ।

5. चूंकि वर्तमान याचिका निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए स्थापित न्याय प्रक्रिया और प्राधिकारी की पूर्व प्रथाओं के अनुसार विचाराधीन उत्पाद मूल अधिसूचना में यथापरिभाषित के समान रहेगा।
6. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क उप शीर्ष 29181520 के अधीन आती है। तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। शुल्क लगाने और संग्रहण के लिए वस्तुओं का विवरण लागू होगा।

ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. निर्णायक समीक्षा के लिए अनुरोध मै. पोसी फार्माचेम प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है और याचिकाकर्ता को नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग माना जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता नियम 5 के अधीन स्थिति संबंधी परीक्षण को भी पूरा करता है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

8. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ग. शामिल देश

9. चूंकि वर्तमान याचिका एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए संबद्ध देशों का दायरा मूल जांच में संबद्ध देश तक सीमित है। अतः वर्तमान याचिका चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के विरुद्ध है।

घ. प्रक्रिया

10. इस समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना स. 14/23/2013-डी जी ए डी दिनांक 26 फरवरी, 2015 जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे।
11. इस समीक्षा में नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के सभी उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

ड. जांच की अवधि (पीओआई)

12. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई जांच की अवधि (बाद में पीओआई के रूप में संदर्भित) अप्रैल 2018-मार्च 2019 है। हालांकि इस जांच में प्राधिकारी ने पीओआई अप्रैल 2018-जून 2019 (15 महीने) माना है। क्षति जांच अवधि में

2015-16, 2016-17, 2017-18 की अवधि और जांच की अवधि शामिल है। जांच के बाद की अवधि पर भी संभावना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है।

च. सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों में जात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

छ. सूचना प्रस्तुत करना

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ज. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।
17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
18. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त

सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

झ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।
23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2019

Case No. SSR-09/2019

Subject : Initiation of Sunset review of Anti-Dumping investigation concerning imports of Sodium Citrate from China PR.

F. No.7/21/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of "Sodium Citrate", (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country). The Authority vide its final findings No. 14/23/2013-DGAD dated 26th February, 2015 recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the subject country. Duties were imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 19/2015-Customs (ADD) dated 20th May, 2015.

2. And whereas, a petition has been filed by M/s Posy Pharmachem Private Limited (hereinafter referred to as 'petitioners') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of subject goods for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from subject country.

A. Product under Consideration

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Sodium Citrate" the "subject goods" or the "Product under Consideration".

4. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of mono-sodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. Sodium Citrate is the sodium salt of citric acid. Like citric acid, it has a sour taste. Like other salts, it also has a salty taste. In DGAD's Final Findings dated 26th February, 2015 of the original Anti-dumping investigation, the PUC had been defined as,
"The product under consideration for the purpose of present investigation is "Sodium Citrate". Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of monosodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. The product under consideration can also be transacted by the following alternate names:- a. Sodium Citrate b. Tri Sodium Citrate c. Tri Sodium Citrate dihydrate d. Sodium Citrate dihydrate e. Tribasic Sodium Citrate f. Sodium Citrate Tribasic Dihydrate g. Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate h. Sodium Citrate Monobasic Bioextra".
5. The present petition being for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the Product under Consideration remains the same as defined in the original notification.
6. Subject goods fall under customs sub-heading 29181520. However, the said customs classifications are only indicative, and not binding on the scope of the proposed investigations. The description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.

B. Domestic Industry & Standing

7. The request for the sunset review has been filed by M/s Posy Pharmachem Private Limited. The Authority notes that the petitioner holds a major share in total domestic production and the petitioner can be termed as eligible Domestic Industry in terms of the Rule 2(b). Further, the petitioner also passes the test of standing under Rule 5.

Initiation of Sunset Review Investigation

8. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

C. Country Involved

9. The present petition being a sunset review investigation, the scope of the subject countries is confined to the subject country in the original investigation. Therefore, the present petition is against the goods originating in or exported from China PR.

D. Procedure

10. The review will cover all aspects of Final Finding Notification 14/23/2013-DGAD dated 26th February, 2015 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject country.
11. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be mutatis mutandis applicable in this review.

E. Period of Investigation (POI)

12. The period of investigation (hereinafter referred to as 'PoI') provided by the petitioner is April, 2018 to March, 2019. However, PoI considered for the purpose of the present investigations is April, 2018-June, 2019 (15 months). The injury investigation period shall cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation. The period after the investigation period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

F. Submission of information

13. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being

addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi -110001.

G. Submission of Information

14. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

H. Submission of Information on Non-Confidential basis

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as nonconfidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on

being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

I. Inspection of Public File

22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties. Non-cooperation
23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General